

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 13/2022 (राजसमन्द डिक्री)

1. गणेशलाल पिता भगवानलाल, जाति हरिजन, निवासी रेलमगरा मृतक के बजाय:-  
1/1. हीरालाल पिता गणेशलाल, जाति हरिजन, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
- 1/2. मोतीलाल पिता गणेशलाल, जाति हरिजन, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
- 1/3. गीता विधवा गणेशलाल, जाति हरिजन, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. अर्जुनलाल पिता भगवानलाल, जाति हरिजन, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्तगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. रमेशचन्द्र पिता मिठुलाल, जाति हरिजन, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. जीवनलाल पिता मिठुलाल, जाति हरिजन, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. माधुलाल पिता मिठुलाल, जाति हरिजन, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. जगदीशचन्द्र पिता मिठुलाल, जाति हरिजन, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. रोशनलाल पिता मिठुलाल, जाति हरिजन, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. भैरूलाल पिता मिठुलाल, जाति हरिजन, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पॉन्डेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0

अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय व डिक्री

उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा दिनांक

18-04-2022 प्रकरण संख्या 501/2010

उपस्थित (वक्त बहस) :- 1- श्री दुर्गासिंह शक्तावत अभिभाषक अपीलान्तगण

2- श्री पैरोकार सरकार रेस्पॉन्डेण्ट संख्या 1



भू-प्रबन्ध अधिकारी  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर (राज.)



निर्णय

दिनांक 20-02-2024

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्तगण ने एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं मृतक मिटुलाल के पिता भगवान पिता कामड हरिजन को ग्राम सिन्देसरखुर्द में आराजी नंबर 79/1 रकबा 8 बीघा भूमि सन् 1958 में आवंटित हुई थी, जिसका इन्द्राज संवत् 2024 से 2026 में है। भगवान जी की मृत्यु दिनांक 31-05-1976 को हो चुकी है, इसके पश्चात् वादग्रस्त भूमि वादीगण के खातेदारी में अंकित होनी चाहिए थी, किन्तु राजस्व विभाग की गलती से गैरखातेदारी में अंकित हो गयी है। उक्त आराजी नंबर 79/1 रकबा 8 बीघा का नवीन नंबर 109 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, एवं आराजी नंबर 110 रकबा 32 बीघा 8 बिस्वा बनाया गया, जिसमें अन्य नंबर और जोड़े गये। खसरा नंबर 79 के नवीन नंबर 1119/110 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा बनया गया। इस प्रकार खसरा नंबर 1119/110 खसरा नंबर 109 का क्षेत्रफल जोड़ने पर 8 बीघा 2 बिस्वा बनता है, जबकि खसरा नंबर 79 का नवीन रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा बनना चाहिए था। कुल क्षेत्रफल 10 बीघा 8 बिस्वा में से 8 बीघा 2 बिस्वा घटाने पर शेष रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा नवीन नंबर 110 में सम्मिलित कर दिया गया। सेटलमेन्ट को गत पैमाईश को ही दोहराना चाहिए था, रकबा कम या बिलानाम दर्ज करने का सेटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार नहीं है तथा इस प्रकार के अंकन वादीगण के मुकाबले शून्य या बेअसर है। अतः आराजी नंबर 109 एवं 1119/110 में से 10 बीघा 8 बिस्वा का वादीगण को 2/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 8 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन किया जावे।



प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जबकि अन्य प्रतिवादीगण द्वारा भी खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर विशेष कथन में निवेदन किया कि विवादित आराजी नंबर 109 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा पर कब्जा मीटुलाल के समय से प्रतिवादीगण का चला आ रहा है तथा लाखों रुपये खर्च कर प्रतिवादीगण ने उसे काबिल काश्त बनाया है। प्रतिवादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदार हो चुके हैं। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

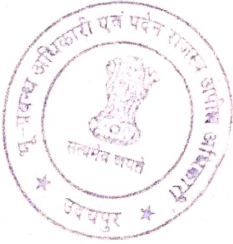
अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में 8 तनकियां कायम की तथा तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 18-04-2022 से

शुभ-प्रबुद्ध अधिकारी  
शुभ-पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
लखनऊ (राज.)

वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्त/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पॉन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 2 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलाश कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील में वर्णित तथ्यों को वर्तमान बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि सेटलमेन्ट को पैमाईश के दौरान पूर्व इन्द्राज को ही दोहराना होता है, इन्द्राज परिवर्तन का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्तगण के पिता भगवानलाल की मृत्यु पर मीटुलाल ने विरासत का नामान्तरकरण मिलीभगत से अपने अकेले के नाम स्वीकृत करवा लिया, जबकि मौके पर भगवानलाल के तीनों पुत्रों का 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार कब्जा चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के अनुसार तनकियों का विवेचन नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 अनुसार तनकियों का पृथक-पृथक विवेचन नहीं कर निबंधात्मक रूप से तनकी नंबर 1 से 3 अपीलान्त/वादीगण के विरुद्ध निर्णित करने में भूल की है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्त/वादीगण द्वारा चाड़ा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे।



उक्त बहस का जवाब देते हुए पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने सभी तनकियों पृथक-पृथक विवेचन कर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्त/वादीगण ने आराजी नंबर 79/1 रकबा 8 बीघा अपने पिता भगवानलाल को वर्ष 1958 में आवंटित होने का कथन किया है, किन्तु इस बाबत उनके द्वारा किसी प्रकार का आवंटन आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त भूमि भगवानलाल को आवंटन से प्राप्त हुई थी। इसके अलावा अपीलान्त/वादीगण ने सेटलमेन्ट के दौरान उसके खाते में रकबा कम दर्ज होने का कथन किया है, किन्तु मूल आराजी नंबर 79 का कुल रकबा कितना था तथा सेटलमेन्ट के दौरान इसके कौन-कौन से आराजी नंबर बने तथा किसी आराजी में कितना रकबा गया, इस बाबत भी उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी का वाद स्वयं के पैरों पर खड़ा होता है, जिसे वादीगण साबित करने में

OW

श्री-प्रबन्ध अधिकारी  
इवं पदेन राजसूय अपील न्यायालय  
उदयपुर (राज.)

असफल रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रत्येक तनकी पर पृथक-पृथक विवेचन करते हुए अपीलान्त/वादीगण का वाद साबित नहीं पाये जाने के आधार पर खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18-04-2022 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्ली पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 20-02-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।



(प्रदीप सिंह-सांगावत)  
 प्रबन्ध अधिकारी  
 एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 उदयपुर

**डिगरी व सीगे अपील**  
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....  
व इजलास .....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

गणेशलाल मृतक के बजाय हीरालाल जी, बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,  
पिता गणेशलाल, जाति हरिजन, निवासी व रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य  
तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं.....13/2022.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी .....  
.....रेलमगरा..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह.....04.....2022.....

**दावा बाबत**

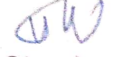
यह अपील व तारीख.....20.....माह.....02.....सन् 2024 रूबरू.....पक्षकारान  
व हाजरी.....श्री दुर्गासिंह शक्तावत.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री पैरोकार सरकार

.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन  
होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18-04-2022  
यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये ..... X.....  
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....20.....माह.....02.....2024  
को जारी किया गया।



  
(प्रदीप सिंह सांगावत)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर

**खर्चा अपील**

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोंडेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... ..			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा .....			2. स्टाम्प अर्जी .....		
3. इजराय हुक्मनामा .....			3. इजराय हुक्मनामा .....		
4. वकील फीस बाबत .....			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान .....			मीजान .....		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये  
दिलाया गया हो।